LOK SABHA

Thursday, April 25, 1968/Vaisakha 5, 1890 (Saka)

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[Mr. Speaker *in the Chair*]

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

मोटे अनाज का बिना रोक-टोक लाना व ले जाना

+

*1442. **श्री बृज भूषण लाल :**
श्री कंवर लाल गुप्त :
श्री भारत सिंह चौहान :
श्री टी० पी० शाह :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चने, जौ तथा अन्य मोटे अनाजों के लाने ले जाने पर से प्रतिबन्धों के हटा देने तथा दिल्ली को भी शामिल करके उत्तरी जोन को बड़ा बना देने का क्या प्रभाव पड़ा है;

(ख) क्या इससे किसानों को तथा उपभोक्ताओं को लाभ हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार खाद्य जोनों को पूर्णतया समाप्त करने के प्रश्न पर विचार करने का है ?

THE MINISTER OF FOOD AND AGRICULTURE (SHRI JAGJIWAN RAM) : (a) and (b). The decision to make movement of gram and barley free in the country and to form larger Northern Zone was given effect to only on 28.3.1968. It is too early to assess the effect of the relaxations on movement particularly as the Rabi crop has just started coming into the market.

(c) There is no proposal at present for abolition of Food Zones altogether. The question of continuance or otherwise of the zonal restrictions may be considered in the conference of Chief Ministers before the Kharif harvest.

श्री बृज भूषण लाल : आज उत्तर प्रदेश एक डेफिसिट प्रान्त है। उसने 1967-68 में अनाज के बारे में केन्द्रीय सरकार से जो मांग की थी, उसकी 75 परसेंट भी केन्द्रीय सरकार ने नहीं दिया। क्या मंत्री महोदय उत्तर प्रदेश को भी दिल्ली, हिमांचल प्रदेश, हरियाणा और पंजाब के जोन में शामिल करने पर विचार कर रहे हैं ?

श्री जगजीवन राम : विचार करने के बाद ही अभी यह फैसला हुआ है कि अभी जोन यहीं तक सीमित रहें। लेकिन मैं सदन को बताना चाहता हूँ कि यह खुशी की बात है कि इस साल उत्तर प्रदेश में रबी की फसल बहुत अच्छी हुई है और गेहूँ के दाम पंजाब के दामों के मुकाबले में हैं।

श्री प्रकाश वीर शास्त्री : अभी समाचार पत्रों में आया है कि सुरक्षित भंडार के लिए पंजाब सरकार का जो कोटा नियत किया गया था, वह उससे लगभग दुगुना कोटा देने के लिए तैयार है। वैसे सभी देश के प्रायः सभी भागों में फ़सल अच्छी हुई है। इस स्थिति में सरकार क्यों नहीं इन जोन्स की दीवारों को हटा देती है, ताकि देश में खाद्यान्नों का उन्मुक्त आवागमन हो और सबको समान रूप से गेहूँ उपलब्ध हो सके ?

श्री जगजीवन राम : इन सभी पहलुओं पर विचार करके मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में

यह फैसला लिया गया था और चूंकि यह फैसला अभी लिया गया है, इस लिए तुरन्त ही उस में कोई रद्दो-बदल करने की आवश्यकता दिखाई नहीं देती है ।

श्री क० ना० निवारी : अभी एक माननीय सदस्य ने उत्तर प्रदेश को उत्तरी जोन में शामिल करने के बारे में पूछा है । मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या वह बिहार की स्थिति को दृष्टि में रखते हुए उसको भी उस जोन में शामिल करने की कृपा करेंगे ?

श्री जगजीवन राम : जैसा कि मैंने कहा है, रबी के लिये जोन के मामले पर फिर से विचार करने का अभी कोई प्रस्ताव नहीं है ।

SHRI RANGA : I am glad that the Minister concerned was favourable to extending the area of the zone in spite of the protest from some of the local Governments and, in the end, he succeeded in getting Delhi also included. What steps are being taken to ensure that the producers' interested are properly protected and, secondly, why is it that Government has expressed the fear that they may not be able to procure right upto the target of 3½ million or 7 million tonnes in view of the fact that there is a bumper crop and the peasants are too anxious to sell and the Food Corporation should be capable of taking in what all surpluses the peasants are willing to hand over ?

SHRI JAGJIWAN RAM : I will first explain the point about the procurement figures. The figure of 7 million tonnes was for the Kharif crop. It was not the total procurement and what the apprehension was expressed, taking into consideration the political situation and other factors that the target of Kharif procurement may not reach 7 million tonnes. We have fixed the target of Rabi procurement as 2 million tonnes, the total being 9 million tonnes. So far as Rabi crop is concerned, I have no doubt that the target may even be exceeded.

So far as the farmers' interest is concerned, we have fixed the procurement price of Rabi, which is regarded as a good incentive price and the efforts are being made to see that by procurement, through the public agencies, whatever stock is offered is purchased at the procurement price and that the price are not permitted to fall below that.

श्री शिव नारायण : सरकार की पालिसी स्टेट ट्रेडिंग और प्रोक्युरमेंट की है । जोन के झगड़े को छोड़ दीजिये, लेकिन मैं यह जानना चाहता हूं कि सरकार इस पालिसी को कब तक कार्यान्वित कर सकेगी, ताकि सारा गल्ला उस के हाथ में रहे ।

श्री जगजीवन राम : जैसे-जैसे गल्ला बाजार में आता रहेगा, वैसे-वैसे हम खरीदते जायेंगे ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : दक्षिण के चार राज्यों का एक चावल क्षेत्र बनाने का प्रस्ताव बहुत पुराना है । क्या मुख्य मन्त्रियों के सम्मेलन में उस प्रस्ताव पर भी विचार किया गया और क्या खाद्य मंत्री महोदय उन कारणों पर प्रकाश डालने का कष्ट करेंगे, जिनके आधार पर वह प्रस्ताव अस्वीकृत कर दिया गया ।

श्री जगजीवन राम : जैसा कि मूल प्रश्न के उत्तर में बताया गया है, जहां तक और जोन्ज का प्रश्न है, जिनका सम्बन्ध खरीफ की उपज से है, जब खरीफ की फसल तैयार होगी, उस वक्त उस पर विचार किया जायेगा । अभी मुख्य मंत्रियों का जो सम्मेलन हुआ था, उसमें सिर्फ रबी पर विचार किया गया था ।

SHRI NITIRAJ SINGH CHAUDHARY: In spite of the removal of restriction in the movement of gram and barley, the State of Madhya Pradesh is not allowing the movement of these grains. The Railways are also not booking these goods. May I know what steps the Central Government is taking to get this decision implemented ?

SHRI JAGJIWAN RAM : As we have informed the House earlier, any restriction placed by any State Government, in contravention of the Central direction, will be illegal and *ultra vires*. If any

party has any grievance, he can seek the requisite remedy.

SHRI HEM BARUA : Is it not a fact that the question of abolition of zonal restriction on food was discussed in the last meeting of the Chief Ministers of Rabi crop areas and that they were in general agreement so far as the abolition of zonal restrictions is concerned and, if so, may I know why is it that the Government have not acted on the advice of the Chief Ministers?

SHRI JAGJIWAN RAM : The Government has acted on the advice and the consensus that emerged in the Chief Ministers' Conference.

श्री अमृत नाहाटा : यह सही है कि जब तक देश खाद्यान्न के मामले में पूरी तरह से आत्म-निर्भर नहीं हो जायेगा, जब तक सरकार के पास बहुत बड़ा वफर स्टाक नहीं हो जायेगा, तब तक इन जोन्ज को रखना आवश्यक है, चाहे देश का व्यापारी वर्ग उनके एबालिशन की मांग करे। हमारे देश में जो राज्य हैं, वे भाषा के आधार पर बने थे; वे खाद्यान्न के उत्पादन के आधार पर नहीं बने थे। इस का नतीजा यह है कि जो स्टेट सरप्लस है, उसके साथ डेफ़िसिट स्टेट्स ऐसा बर्ताव करती हैं, जैसे कि सरप्लस होना कोई अपराध है; सब उन पर टूट पड़ते हैं। क्या सरकार एक दो डेफिसिट स्टेट्स और एक दो सरप्लस स्टेट्स को मिलाकर देश में चार पांच मल्टी-स्टेट जोन्ज बनाने के प्रश्न पर विचार करेगी, ताकि देश भर में खाद्यान्न का उचित वितरण हो सके ?

श्री जगजीवन राम : जैसा कि मैंने कई दफा सदन में बताया है, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और जम्मू-काश्मीर का जो ज़ोन बनाया गया है, वह तो मल्टी-स्टेट ज़ोन ही है।

श्री अब्दुल गनी डार : वजीर साहब ने श्री प्रकाशवीर शास्त्री के सवाल के जवाब में फरमाया चूंकि जोन्ज के बारे में अभी हमने फैसला किया है, इस लिए इस पर दोबारा गौर करने की जरूरत नहीं है, मैं जानना चाहता हूं कि क्या आप इस बात का भरोसा दिलायंगे कि पंजाब में जहां बहुत ज्यादा गेहूं पैदा हुआ है, वहां के किसानों को जो मुनासिब निर्ख है, उस से कम निर्ख नहीं मिलेगा और सरकार इस मामले में पूरी मदद करेगी जिससे कि निर्ख गिरने न पायें, ताकि किसानों को पिछले दो सालों में जिस तबाही का सामना करना पड़ा है, अब थोड़ी सी सहूलियत उन को मिल सकेगी ?

وزیر صاحب نے شری پرکاش ویر شاستری کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ چونکہ زونز کے بارے میں ابھی ہم نے فیصلہ کیا ہے۔ اسلئے اس پر دوبارہ غور کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں جاننا چاہتا ہوں کہ کیا آپ اس بات کا بھروسہ دلائینگے کہ پنجاب میں جہاں بہت زیادہ گیہوں پیدا ہوا ہے وہاں کے کسانوں کو جو مناسب نرخ ہے اس سے کم نرخ نہیں ملے گا۔ اور سرکار اس معاملے میں پوری مدد کریگی۔ جس سے کہ نرخ گرنے نہ پائیں۔ تاکہ کسانوں کو پچھلے دو سالوں میں جس تباہی کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ اب تھوڑی سی سہولیت انکو مل سکے۔

श्री जगजीवन राम : मैंने इस सवाल का जवाब दिया है, पंजाब का किसान तो पिछले साल भी अच्छा ही रहा है। जितना भी अनाज मिलेगा, जो दाम हमने उपलब्धि के निश्चित किये हैं, उस पर खरीद लेंगे।

SHRI SRADHAKAR SUPAKAR : So far as the procurement is concerned, the season for procurement of rice is not yet over. But we hear from newspaper reports that a huge quantity of rice is going to be imported from abroad. How far is this news correct ?

SHRI JAGJIWAN RAM : Does it arise out of this question ?

SHRI SRADHAKAR SUPAKAR : Yes, because procurement was discussed ; answer for procurement was given earlier during this Question. That is why I put this question- Is there a scheme for procuring a large quantity of rice from abroad, although the period of procurement is not yet over ?

SHRI JAGJIWAN RAM : Yes, Sir. It is proposed, from the very beginning,

to import some rice because we are still deficit in rice.

श्री मधु लिमये : अध्यक्ष महोदय, जहां तक चने का सवाल है, उसको बिना रोक लाने तथा ले जाने के बारे में मध्य प्रदेश की गैर कांग्रेसी सरकार और केन्द्र की कांग्रेसी सरकार के बीच में बड़ी अखबारी लड़ाई चल रही है। आपने कहा है कि उन को ऐसा अधिकार नहीं है और मध्य प्रदेश की सरकार ने कहा है कि हमने रोक नहीं लगाई है। इसके बारे में वास्तविक स्थिति क्या है और मध्य प्रदेश से इन दिनों में कितना चना बाहर गया है क्या सरकार के पास इसकी सूचना है ?

श्री जगजीवन राम : जहां तक माननीय सदस्य के प्रश्न के पहले भाग का सम्बन्ध है, मैंने यहां सदन में एक वक्तव्य दिया था और उस में मामला साफ कर दिया गया था। जब परमिट और लाइसेंस नहीं रहता है तब, जैसा कि मध्य प्रदेश गवर्नमेंट का कहना है, उस का कोई हिसाब रखना कि कितना बाहर गया सम्भव नहीं है।

SHRI ANANTRAO PATIL: After the formation of a larger Northern Zone, the concerned States have been benefited to a larger extent. In view of that, may I know from the Government whether they propose to form a larger Southern Zone comprising the States of Madhya Pradesh, Gujarat, Maharashtra, Mysore, Andhra Pradesh, etc. ?

SARI JAGJIWAN RAM: I have already answered that.

श्री झारखण्डे राय : मान्यवर, मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में बराबर इस बात की आवाज उठाई गई कि खाद्य जोन अलग-अलग सूबों का समाप्त कर दिया जाय, इसके साथ ही भारत सरकार राज्य सरकारों की राय से अलग अलग स्टेट में लैवी भी दोनों फसलों में इकट्ठा कर रही है। ऐसी हालत में कौन सा ऐसा मजबूत आधार है कि अलग-अलग सूबों का अलग-अलग जोन कायम रखा जाय-यही मैं जानना चाहता हूं ?

श्री जगजीवन राम : यह तो मैंने बार'बार दोहराया है कि मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में इन प्रश्नों पर विचार होता है और वहां जो प्रायः सहमति होती है, उस के ऊपर अमल किया जा रहा है। जहां तक लैवी का प्रश्न आपने उठाया हमने किसी भी सरकार को किस तरह से लैवी लगाई जाय, यह नहीं कहा है। हमने उन से इतना ही कहा है कि इतना अनाज आपको उपलब्ध कर लेना चाहिए। कैसे करेंगे यह उनके ऊपर निर्भर करता है।

श्री विभूति मिश्र : यह सरकार कहती है कि अगर हम जोन नहीं बनायें, तो प्राइवेट ट्रेडर्स बीच में चले आयेंगे। प्राइवेट ट्रेडर्स के नाम से यह सरकार किसानों को मारती है। सरकार जो प्रोक्योरमेंट प्राइस रखती है, फ्री-मार्केट से उसकी आधी कीमत होती है। मैं चाहता हूं कि किसानों के हित में सरकार प्राईवेट ट्रेड को बन्द कर दे और किसानों को कहे कि फ्री-मूवमेंट खुला रहेगा, जो चाहे ले जाय। सरकार किसानों पर लेवी लगाती है, लेकिन फैक्टरी वालों पर कोई लेवी लागू नहीं करती, कपड़ा और दूसरे सामान हमको सही दामों पर सप्लाई नहीं करती है। मैं जानना चाहता हूं कि सरकार किसानों के हित में कौन सा उपाय सोच रही है कि जिससे किसानों को उचित कीमत मिल सके ?

श्री जगजीवन राम : मैंने बार-बार बताया है कि इस वर्ष जो रबी का दाम निश्चित किया गया है, वह बिलकुल मुनासिब और लाभकारी दाम है। इसको अगर कोई यह समझता है कि यह कम दाम है, तो मैं समझता हूं कि वह मुनासिब नहीं समझता है। जहां तक उद्योगों का सम्बन्ध है, बहुत से उद्योग ऐसे हैं जिनकी सारे उत्पादन के ऊपर दाम का नियन्त्रण है इस पहलू को नहीं भूलना चाहिए। यहां पर

यदि लेवी है तो उत्पादन के एक छोटे से अंश पर है, बाकी अंश किसान के लिए स्वतंत्र रहता है चाहे जिस दाम पर बेचे। लेकिन जहां तक रबी का सवाल है गेहूं का दाम जो निर्धारित किया गया है, मैं मानता हूं कि काफी मुनासिब और प्रोत्साहित करने वाला दाम है।

श्री कंवर लाल गुप्त : दिल्ली में सरकार की इस नीति से यह असर हुआ है कि करीब करीब 15-20 रु० क्विंटल दाम गिर गये हैं। नतीजा यह हुआ है कि राशनिंग में जो 12-13 हजार क्विंटल अनाज था, उसको कोई लेता नहीं था और अब सरकार ने उसकी कीमत नीचे गिराकर बेचा है। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि दिल्ली की राशनिंग व्यवस्था के बारे में आगे उनका क्या रुख है- आया इन्फ़ार्मल राशनिंग रहेगा या फेअर प्राइस शाप्स रहेंगी क्या व्यवस्था सरकार सोच रही है ? क्या यह सही है कि हरियाणा और पंजाब में सरकार प्रोक्योरमेंट नहीं कर रही है और वहां पर दाम नीचे गिर रहे हैं। कभी करती है और कभी नहीं करती है। क्या आप फर्म एंशोरेन्स देंगे कि जो भाव आपने निश्चित किये हैं, सरकार उस भाव पर जरूर खरीदेगी ?

MR. SPEAKER : I think he has already assured that the prices will not be allowed to fall down ?

श्री जगजीवन राम : मैं तो बराबर कह रहा हूं लेकिन व्यापारियों का एक अपना लोबी है और वह इसलिए है कि यह सारा मामला खुल जाय। वे कुछ इस प्रकार की लोबी तैयार किया करते हैं कि वहां तो 20 रु० गेहूं बिकने लगा, वहां पर 22 रु० बिकने लगा, जब मैं छानबीन करता हूं तो हमको उस दाम में मिलता ही नहीं। अगर गुप्ता जी गिरे हुए दामों पर दिलवा दें तो हम लेने को तैयार हैं, हरियाणा और पंजाब की सरकारें दोनों इस मामले पर तत्पर हैं, खरीदने के लिए तैयार हैं, खरीद भी रही हैं और दाम नहीं गिरने दिया जायेगा, यहां मैंने इस बात को कहा है।

दिल्ली के बारे में फोरमली राशनिंग को खत्म नहीं किया गया है, लेकिन व्यावहारिक तरीके से सभी प्रकार की छूट दे दी गई है। उसको इसलिए रखा गया है कि आज भी शायद माननीय सदस्य को मालूम होगा हम जो बाहर से आये हुए गेहूं का आटा दिल्ली में देते हैं, उस आटे की खपत काफी हो रही है। इसके मायने यह हैं कि जो सीमित साधन और आय वाले लोग हैं, आज भी इस पर निर्भर करते हैं, अतः उस को बिल्कुल हटा देने की मंशा अभी नहीं है।

SHRI MANUBHAI PATEL : In view of the experience gained by removing the restrictions on the movement of course grains like gram, jowar, etc., and in view of the bumper crop of wheat in wheat area, will the Government consider removing restrictions on the movement of wheat also at the earliest ?

SHRI JAGJIWAN RAM : No ; the Government will not consider that.

SHRI LOBO PRABHU : The statement of the Minister that his Ministry would be very ready to buy grain at a price lower than the statutory price apparently has not been compared by him with the daily prices reported in the papers, for instance, according to the report today, the price of Mexican wheat is Rs. 60 to 66 per quintal. Am I to infer that this information is not available to the procurement agencies and that they have, therefore, refrained from going and buying that wheat and are inflating the price to the level fixed by the Government ?

SHRI JAGJIWAN RAM : I do not know which Market is being quoted, but sometimes... (*Interruptions*) in regard to some markets, their quotations are on the paper and not on the physical quantity of foodgrains.

SHRI LOBO PRABHU : May I inform him that these quotations have been watched by me over a period of time ?

MR. SPEAKER : Next Question.